नईदुनिया

रामदेव, बालकृष्ण एक हफ्ते के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली ।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण दोनों मौजूद थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनकी माफी का संज्ञान लिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि इस स्तर पर हमने रियायत देने का फैसला नहीं किया है। पीठ ने बालकृष्ण से बातचीत करते हुए उनसे कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते। पीठ से बातचीत करने वाले रामदेव ने भी कहा कि उनका किसी भी तरह से अदालत का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, पीठ ने बालकृष्ण से कहा कि वे (पतंजलि) इतने निर्दोष नहीं हैं कि उन्हें पता ही न हो कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपने पहले के आदेशों में क्या कहा था। पतंजलि भ्रामक मामले में 23 अप्रैल को होगी सुनवाई पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। उस दिन अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इससे पहले मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि रामदेव सार्वजनिक रूप से मामले में माफी मांगना चाहते हैं। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अदालत सुनना चाहती है कि रामदेव और बालकृष्ण क्या कहना चाहते हैं, उन्हें कहिए वे सामने आएं। ऑडियो में कुछ गड़बड़ी होने के कारण बेंच कुछ मिनटों के लिए उठ गई। बेंच ने चुटकी लेते हुए कहा, ऐसा मत सोचिए कि यह हमारी ओर से कोई सेंसरशिप है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पातंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में अब 23 अप्रैल की तारीख तय की। कोर्ट ने उस तारीख को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा है।

न्यूज ब्रीफ

दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में शामिल, एसीआई ने जारी की लिस्ट

नई दिल्ली । दिल्ली हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की सूची में 2023 के लिए 10वें नंबर पर रखा गया है। हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस लिस्ट में टॉप पर है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) वर्ल्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व्यस्त रहने के मामले में दसवें स्थान पर है जबकि दुबई और डलास हवाई अड्डे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सूची जारी करते हुए एसीआई ने यह भी कहा कि 2023 के लिए वैश्विक स्तर पर कुल हवाई यात्रियों का पूर्वानुमान 8.5 बिलियन (850 करोड़) के करीब है, जो पूर्व-महामारी के स्तर से 93.8 प्रतिशत अधिक जबकि 2022 की तुलना में 27.2 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से पांच अमेरिका में हैं। दसवें स्थान पर, दिल्ली हवाई अड्डा है जहां से 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। 2022 में, हवाई अड्डा नौवें स्थान पर था। हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिस्ट में शीर्ष पर है और इसने पिछले साल 10.46 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान की। व्यस्तता के मामले में इसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से होकर 8.69 करोड़ से अधिक हवाई यात्री गुजरे। डलास फोर्थ वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिस्ट में तीसरे स्थान पर जहां से होकर 2023 में 8.17 करोड़ से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। सूची में लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा चौथे स्थान पर, टोक्यो का हनेडा हवाई अड्डा पांचवें नंबर, डेनवर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा छठे, इस्तांबुल हवाई अड्डा सातवें, लॉस एंजिलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आठवें और शिकागो का ओहारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नौवें स्थान पर है। एसीआई दुनिया के हवाई अड्डों काएक व्यापार संघ है।

क्या डेयरी ऋण योजना के तहत नाबार्ड सीधे लोन देता है अफवाहों पर बैंक ने बयान जारी कर साफ की स्थिति

नई दिल्ली । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने नाबार्ड डेयरी ऋण योजना के बारे में फैलाए जा रहे अफवाहों पर एक बयान जारी कर स्थिति साफ की है। नाबार्ड ने स्पष्ट रूप से उन झूठे दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि, वह डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत किसानों को डेयरी व्यवसायों के लिए सीधे ऋण प्रदान करता है। नाबार्ड ने स्पष्ट किया है कि उक्त दावों में दी गई जानकारी पूरी तरह से गलत है। नाबार्ड ने कहा है कि वह एक शीर्ष विकास वित्त संस्थान के रुप में, ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए काम करता है। नाबार्ड कभी भी अलग-अलग किसानों को सीधे ऋण वितरित नहीं करता है। नाबार्ड ने अपने सभी हितधारकों, विशेषकर किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को ऐसी गलत सूचनाओं के संबंध में सावधानी बरतने और उनमें विश्वास करने तथा उनका प्रचार-प्रसार करने से बचने के लिए आग्रह किया है। नाबार्ड ने कहा है कि असत्यापित जानकारी से किसी को भी वित्तीय जोखिम और गलतफहमी हो सकती है। नाबार्ड ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं की सटीक जानकारी नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। नाबार्ड ने कहा है कि संधारणीय आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों और योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास और कृषि को बढ़ावा देने के प्रतिबद्ध है।

2028 तक सेवा क्षेत्र में होगा सबसे अधिक रोजगार का सृजन, ओआरएफ की रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली । ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) ने रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2030: नेविगेटिंग सेक्टोरल ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटेंसी में वर्ष 2028 तक कुल रोजगार में 22 प्रतिशत की वृद्धि और बेरोजगारी में 97 आधार अंकों की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन में सबसे अधिक वृद्धि की उम्मीद है। सेवा उत्पादन में प्रत्येक इकाई वृद्धि के साथ रोजगार में 0.12 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह रिपोर्ट भारत भारतीय बाजार में नौकरियों के भविष्य पर प्रकाश डालती है और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र की भूमिका पर जोर देती है जो रोजगार वृद्धि के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देश 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। रिपोर्ट में तेजी से विकास के लिए तैयार दस उच्च-अवसर वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें डिजिटल सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, उपभोक्ता खुदरा, ई-कॉमर्स, नवीकरणीय ऊर्जा, वैश्विक क्षमता केंद्र और एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम शामिल हैं।

मुखर्जी और चिदंबरम ब्याज दरों को नरम रखने के लिए आरबीआई पर बनाते थे दबाव, पूर्व गवर्नर ने किया दावा

नई दिल्ली ।

प्रणब मुखर्जी और पी. चिदंबरम के नेतृत्व वाला वित्त मंत्रालय ब्याज दरों में नरमी लाने के लिए रिजर्व बैंक पर दबाव डालता था और आम जनमानस में सरकार के प्रति सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने के लिए वृद्धि की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए कहता था। यह दावा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने अपनी किताब में किया है। सुब्बाराव ने अपनी हालिया किताब जस्ट ए मर्सिनरी: नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर में यह भी लिखा है कि सरकार में केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के महत्व को लेकर समझ और संवेदनशीलता कम है। उन्होंने पुस्तक में लिखा है, सरकार और आरबीआई दोनों में रहने के कारण मैं कह सकता हूं कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के महत्व को लेकर सरकार के अंदर कम समझ और संवेदनशीलता है। सुब्बाराव 5 सितंबर, 2008 को पांच साल के लिए आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वित्त सचिव (2007-08) थे। उनके आरबीआई गवर्नर का पद संभालने के कुछ दिन बाह ही 16 सितंबर को अमेरिका का लेहमैन ब्रदर्स दिवालिया हो गया था और यह 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बना था। यह इतिहास की सबसे बड़ी कॉरपोरेट विफलता भी मानी जाती है।

दावा- मूल्यांकन के विपरीत विकास और महंगाई का अनुमान पेश करने को कहा गया

रिजर्व बैंक सरकार की चीयरलीडर शीर्षक वाले एक अध्याय में सुब्बाराव ने बताया है कि सरकार का दबाव सिर्फ रिजर्व बैंक के ब्याज दर के रुख तक सीमित नहीं था। केंद्रीय बैंक पर इस बात के लिए भी दबाव बनाया गया कि वह मूल्यांकन के विपरीत विकास और मुद्रास्फीति के बेहतर अनुमान पेश करे। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा अवसर याद है जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। वित्त सचिव अरविंद मायाराम और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने अपने अनुमानों के साथ हमारे अनुमानों का विरोध किया, जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा था। सुब्बाराव ने कहा कि जो बात उन्हें परेशान करती थी, वह यह थी कि चर्चा लगभग निर्बाध रूप से वस्तुनिष्ठ तर्कों से व्यक्तिपरक विचारों की ओर बढ़ गई। यहां तक सुझाव दिया गया था कि रिजर्व बैंक को उच्च विकास दर और कम मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाना चाहिए ताकि सरकार के पक्ष में सकारात्मक भावनाएं बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा, मायाराम ने एक बैठक में यहां तक कह दिया कि दुनिया में हर जगह, सरकारें और केंद्रीय बैंक आपस में सहयोग कर रहे हैं, यहां भारत में रिजर्व बैंक बहुत उद्दंड है। सुब्बाराव ने कहा कि वे उनकी इस उम्मीद से हमेशा परेशान और नाराज रहे कि आरबीआई को सरकार के लिए चीयरलीडर के रूप में काम करना चाहिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि वह इस बात को लेकर सख्त थे कि रिजर्व बैंक अपने बेहतरीन पेशेवर फैसले में सिर्फ जनता के बीच सकरात्मक भावनाएं बनाने ना भटके।

सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव विकसित देशों में भी

उन्होंने कहा, हमारे अनुमान हमारी नीतिगत रुख के अनुरूप होने चाहिए और वृद्धि व मुद्रास्फीति के अनुमानों के साथ छेड़छाड़ करने से रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता कम होगी। सुब्बाराव ने यह भी कहा कि यह दिलचस्प है, यहां तक कि कुछ हद तक सुकून देने वाला है, कि सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच ये तनाव भारत या उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ही नहीं है बल्कि अमीर देशों में भी ऐसा हेता है। उन्होंने यह भी याद किया कि आरबीआई के नीतिगत रुख को लेकर चिदंबरम और मुखर्जी दोनों के साथ उनका टकराव हुआ था क्योंकि दोनों हमेशा नरम दरों पर जोर देते थे, हालांकि दोनों की शैली अलग थी। सुब्बाराव ने लिखा, चिदंबरम आमतौर पर वकील की तरह अपने मामले में बहस करते थे, वहीं मुखर्जी प्रतिष्ठित और सर्वोत्कृष्ट राजनेता थे। वे अपना नजरिया जाहिर करने के बाद मामले में बहस करने का काम अपने अधिकारियों पर छोड़ देते थे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने याद किया कि अक्टूबर 2012 में चिदंबरम के गृह मंत्रालय से वित्त मंत्री के रूप में लौटने के तुरंत बाद, उन्होंने मुखर्जी शासन की राजकोषीय फिजूलखर्ची को उलटने के लिए ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया था, संभवत: वे ऐसा राजकोषीय सख्ती की भरपाई करने के लिए कर रहे थे। उन्होंने कहा, वह नरम मौद्रिक व्यवस्था चाहते थे और आरबीआई पर ब्याज दर को कम करने के लिए भारी दबाव डाल रहे थे। हालांकि इस मामले में मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सका।

रियलमी पी सीरीज मिडरेंज स्मार्टफोन की धूम, खूबियों के कारण बने ग्राहकों की पहली पसंद

नई दिल्ली ।

चाइनीज कंपनी रियलमी पी सीरीज मिडरेंज स्मार्टफोन बाजार में धूम मचा रही है। रियलमी पी1 प्रो 5जी के केंद्र में एक शानदार 6.7-इंच एफएचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले है। 120एचजेड तक की ताज़ा दर के साथ, यह उपयोगकर्ताओं को एक सहज और गहन सामग्री-देखने का अनुभव प्रदान करता है, जो वास्तव में इसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। देखने के अनुभव के साथ जीवंत डिस्प्ले को उच्च स्तर की चमक समायोजन और 200 हर्ट्ज तक की इंस्टेंट टच सैंपलिंग दर के साथ चमक द्वारा और भी बढ़ाया जाता है। इनोवेशन को एक कदम आगे ले जाते हुए, रियलमी पी1 प्रो 5जी ने अपने प्राइस रेंज में सबसे अच्छा कर्व्ड डिस्प्ले पेश किया है। इसे 20 हजार प्राइस रेंज के तहत सबसे अच्छे स्मार्टफोन के रूप में पेश किया गया है।

यह डिज़ाइन न केवल आकर्षक है, बल्कि पकड़ भी शानदार है। डिवाइस को पकड़ने और उपयोग करने में मजा आता है। यह रियलमी पी सीरीज़ को गेमिंग के शौकीनों और मल्टीमीडिया उपभोक्ताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है, जो सहज और बेहतर दृश्य को महत्व देते हैं। आज के डिजिटल युग में आंखों के स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करते हुए, रियलमी पी सीरीज उन सुविधाओं से लैस है, जो यूजर्स को अपनी आंखों पर दबाव डाले बिना या आंखों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना लंबे समय तक डिवाइस का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, रियलमी पी सीरीज़ बैकलाइट ब्राइटनेस एडजस्टमेंट में बेहतर परिशुद्धता प्रदान करके यूजर के आराम को प्राथमिकता देती है। यह सुविधा स्क्रीन पर एक सहज और लगातार भौतिक चमक आउटपुट सुनिश्चित करती है, जो विभिन्न प्रकाश स्थितियों में आरामदायक ढंग से देखने में सक्षम बनाता है। रियलमी पी1 5जी मीडियाटेक डाइमेंशन 7050 5जी चिपसेट से भी सुसज्जित है, जो ग्राफिकल प्रदर्शन और बढ़ी हुई प्रोसेसिंग पावर में पर्याप्त वृद्धि देने का वादा करता है।

एफडी पर सीनियर सिटिजन से 27000 करोड़ टैक्स, केबल ब्रॉडबैंड यूजर 20 फीसदी बढ़े; हर माह 24 जीबी डेटा की खपत

नई दिल्ली/मुंबई।

देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कहा कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) से अर्जित ब्याज पर वरिष्ठ नागरिकों से 27 हजार करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। एसबीआई के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में जमा की कुल राशि 143 फीसदी बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के अंत में 14 लाख करोड़ से 34 लाख करोड़ हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च ब्याज दरों के कारण वरिष्ठ नागरिकों के बीच सावधि जमा में निवेश करने की रुचि बढ़ी है, क्योंकि इसी अवधि में सावधि जमा खातों की कुल संख्या 81 प्रतिशत बढ़कर 7.4 करोड़ हो गई है। एसबीआई के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इनमें से कम से कम 7.3 करोड़ खातों में 15 लाख रुपये से अधिक की राशि है, और यह मानते हुए कि जमा पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलता है, वरिष्ठ नागरिकों ने अकेले ब्याज के रूप में वित्त वर्ष 24 में 2.7 लाख करोड़ कमाए हैं। इसमें बैंक जमा से 2.57 लाख करोड़ रुपये और वरिष्ठ नागरिक बचत

योजना से शेष शामिल हैं। केबल ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 20 फीसदी बढ़ी देश में केबल ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 20 फीसदी (29 फरवरी, 2024) बढ़कर 91.6 करोड़ हुई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या फरवरी 2023 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। कुल मिलाकर, यह संख्या 2018 में 39.2 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2024 में 91.6 करोड़ हो गई। आंकड़ों के मुताबिक, यह संख्या में 2021 में 16 प्रतिशत, 2022 में 19 प्रतिशत और 2023 में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन के प्रसार ने 95 फीसदी भारतीय आबादी को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।

टेस्ला में जा सकती है 14,000 कर्मचारियों की नौकरी, कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का इस्तीफा

नई दिल्ली ।

एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है। कंपनी भूमिकाओं के दोहराव का हवाला देते हुए अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक की छंटनी करने की योजना पर काम कर रही है। अगर यह फैसला लागू किया जाता है तो इससे 14,000 लोगों की नौकरी जा सकती है।

एक आंतरिक ईमेल में, सीईओ मस्क ने कहा कि तेज विकास के कारण कंपनी में भूमिकाओं का दोहराव हुआ है और विकास के अगले चरण के लिए लागत में कमी जरूरी हो गई है। मस्क ने लिखा, जैसा कि हम कंपनी को विकास के अगले चरण के लिए तैयार करते हैं, ऐसे में

लागत में कटौती समेत उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनी के हर पहलू को देखना बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रयास के तहत हमने संगठन की गहन समीक्षा की है और वैश्विक स्तर पर अपने कर्मचारियों की संख्या को 10 प्रतिशत से अधिक घटाने का कठिन निर्णय लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं बहुत अधिक पसंद नहीं करता हूं, लेकिन यह किया जाना चाहिए।

टेस्ला की ओर से यह घोषणा ऑटो डिलीवरी में गिरावट की सूचना देने के कुछ दिनों बाद की गई है। कंपनी ने मांग को बढ़ाने के लिए अपने ईवी की कीमतों में कटौती का एलान किया है। टेस्ला के मुखिया एलन मस्क का इस महीने की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। उन्मीद है कि इस दौरान वे भारत में टेस्ला का नया प्लांट खोलने की घोषणा करें। उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट किया था, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने के लिए उत्सुक हूं!।

टेस्ला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ड्रू बग्लिनो ने दिया इस्तीफा

टेस्ला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ड्रू बग्लिनो ने कार निर्माता की नौकरी में कटौती के सबसे बड़े दौर के बीच कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। इलेक्ट्रिक-वाहन की मांग में कमी के बीच कंपनी ने अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक की कटौती का प्लान बताया है।

सोना ऑलटाइम हाई, 10 ग्राम की कीमत 73,514

ईरान-इजराइल टकराव से 16 दिन में दाम 4,550 बढ़े, इस साल अब तक 10,212 महंगा हुआ

नई दिल्ली।

सोने ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक, मंगलवार को 10 ग्राम सोना 701 रुपए महंगा होकर 73,514 रुपए का हो गया है। 1 अप्रैल को इजराइल-ईरान तनाव शुरू हुआ था तब से 16 दिन में सोने के दाम 4,550 रुपए बढ़ गए हैं।

चांदी में भी आज तेजी देखने को मिली है। एक किलो चांदी का भाव 180 रुपए बढ़कर 83,632 रुपए हो गया है। इससे पहले 12 अप्रैल को चांदी ने 83,819 रुपए का हाई बनाया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इनके दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

सिर्फ 15 दिन में ही सोना 4,550 रुपए महंगा हुआ - इजराइल-ईरान तनाव 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। तब सोने की कीमत 68,964 पर था। वहीं अब यानी 16 अप्रैल को ये 1 जनवरी को इसकी कीमत 73,514 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। यानी सिर्फ 15 दिनों में ही 4,550 रुपए महंगा हो चुका है। इजराइल-ईरान तनाव के चलते सोने में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है।

बीते सालों में हुई जंग और मंदी में सोने-चांदी का क्या ट्रेंड रहा है - जंग के दौरान सोने की कीमतों में हमेशा उछाल देखा गया है। 1990-91 के दौरान गल्फ वॉर के दौरान सोने की कीमतों में उछाल आया था, लेकिन यह शॉर्ट टर्म था। इसी तरह 2003 में इराक युद्ध के दौरान सोने की कीमतों में तेजी आई थी।

कोरोना महामारी के कारण भारत समेत अन्य देशों में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था। तब 10 ग्राम सोने के दाम 41,000 रुपए के करीब थे। अगस्त तक दाम बढ़कर 55,000 के करीब तक पहुंच गए। हालांकि, बाद में इसमें गिरावट आई थी और दाम 50,000 से

नीचे आ गए थे। रूस-यूक्रेन जंग के समय भी सोने में तेजी आई। 24 फरवरी 2022 को रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। 7 मार्च 2022 को सोने की कीमतों में लगभग 1000/10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। 22 कैरेट सोने की कीमत 49,400/10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 53,890/10 ग्राम हो गई।

इजराइल-हमास जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। तब सोने की कीमत 57,000 के करीब थी। 1 नवंबर तक कीमत बढ़कर 61,000 के करीब पहुंच गई। वहीं 1 जनवरी को कीमत 63,000 और अब 10 ग्राम सोने की कीमत 73,500 के पार पहुंच गई है।

सोना 75 हजार और चांदी 1 लाख तक पहुंच सकती है - मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, आने वाले दिनों में सोने में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके चलते इस साल के आखिर तक सोना 75 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि अगले कुछ महीनों तक चांदी में तेजी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट में कहा कि हम चांदी में निवेश करने की सलाह देते हैं और मीडियम से लंबी अवधि में 92,000 रुपए और उसके बाद 1 लाख रुपए पहुंच सकता है। फर्म ने 75,000 रुपए की तरफ होने वाली गिरावट पर और निवेश की सलाह दी है।

साढ़े 3 महीने में 10,212 रुपए बढ़े सोने के दाम - इस साल अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 10,212 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपए पर था। ये 63,302 रुपए प्रति ग्राम से 73,514 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 73,395 रुपए प्रति किलोग्राम से 83,632 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

युद्ध या मंदी जैसी स्थिति में सोने-चांदी की कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं - कोई भी जंग जियोपॉलिटिकल इक्वेशन्स खराब कर सकती है। ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित कर सकती है, महंगाई बढ़ा सकती है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लोगों के भरोसे को कम कर सकती है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017